सत्यमेव जयते

महाराष्ट्र के राज्यपाल

सम्माननीय श्री. आचार्य देवव्रत

का

अभिभाषण

महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल का मुम्बई में संयुक्त अधिवेशन

२३ फ़रवरी २०२६

सम्माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय एवं राज्य विधानमंडल के सम्माननीय सदस्यगण,

वर्ष दो हजार छब्बीस में, राज्य विधानमंडल के इस प्रथम सत्र में, आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है ।

२. मेरी सरकार, राज्य के लोगों की सेवा में राजमाता जिजाऊ, छत्रपति शिवाजी महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब अम्बेड़कर, भगवान बिरसा मुंडा, महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांतिज्योति सावित्रीबाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर, राजर्षि छत्रपति शाहू महाराज और कई अन्य महान नेताओं और समाज सुधारकों के उच्च आदर्शों का निरंतर अनुसरण कर रही है।

३. मेरी सरकार, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद को सुलझाने के लिए वचनबद्ध है और इस विवाद को सुलझाने के लिए सम्माननीय उच्चतम न्यायालय में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए विख्यात अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। मेरी सरकार, सीमावर्ती क्षेत्रों में रहनेवाले मराठी-भाषी लोगों के लिए शैक्षणिक, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है।

४.	महाराष्ट्र यह, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने के लिए पसंदीदा राज्य है और देश का एक अग्रणी औद्योगिक राज्य होने से महाराष्ट्र का देश के कुल सक़ल घरेलु उत्पाद में, तेरह दशमलव पाँच प्रतिशत से अधिक योगदान है।

महाराष्ट्र को वर्ष दो हजार चौबीस-पच्चीस में, देश में सबसे अधिक एक लाख, चौंसठ हजार, आठ सौ पचहत्तर करोड़ रुपयों का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है जो भारत में प्राप्त कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के उनतालीस प्रतिशत है। महाराष्ट्र को दो हजार पच्चीस-छब्बीस के वित्तीय वर्ष के प्रथम छमाही में, इक्यानवे हजार, तीन सौ सैंतीस करोड़ रुपयों का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है।

मेरी सरकार ने, जनवरी, दो हजार छब्बीस में स्विट्झर्लंड़ के दावोस में हुए विश्व आर्थिक परिषद में, अठराह देशों की विभिन्न कंपनीयों से लगभग तीस लाख करोड़ रुपयों के निवेश सहमति-करार किये हैं। इससे, चालीस लाख रोजगार निर्माण होने में मदद होगी।

५.	मेरी सरकार ने, "विकसित महाराष्ट्र-दो हजार सैंतालीस" के लिए एक व्यापक और नीतिगत कार्ययोजना तैयार की है और राज्य की अर्थव्यवस्था को दो हजार सैंतालीस तक पाँच ट्रिलियन डॉलर्स तक बढ़ावा देने के लिए “व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट” (Vision Management Unit) स्थापित किया है।

६.	मेरी सरकार ने, वर्ष दो हजार छब्बीस से दो हजार तीस की अवधि के लिए, "महाराष्ट्र उद्योग, निवेश एवं सेवा नीति -दो हजार पच्चीस" की घोषणा की है ।इस नीति

के माध्यम से सत्तर लाख पचास हजार करोड़ रुपयों का निवेश आकर्षित करने और लगभग पचास लाख प्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है।

इस प्रकार, मेरी सरकार ने, राज्य में विभिन्न उद्योंगों को बढ़ावा देने और रोजगार निर्माण करने के लिए, "बांस उद्योग नीति-दो हजार पच्चीस", "रत्न और आभूषण नीति-दो हजार पच्चीस", "ॲनिमेशन, व्हिजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सटेंडेड रिॲलिटी नीति- दो हजार पच्चीस" (Animation, Visual Effects, Gaming, Comics and Extended Reality Policy 2025)और "वैश्विक सामर्थ्यता केंद्र नीति-दो हजार पच्चीस" की घोषणा की है।

७. मेरी सरकार, गड़चिरोली जिले को स्टील हब (Steel Hub) और पूर्वी विदर्भ को स्टील कॉरिडॉर (Steel Corridor) के रूप में विकसित कर रही है।

मेरी सरकार ने, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से भूखंडों का पारदर्शि आवंटन करने के लिए, “एम आय डी सी इंडस्ट्रीयल लँड ॲप्लीकेशन अँड अलॉटमेंट पोर्टल (मिलाप)" (MIDC Industrial Land Application and Allotment Portal) नामक एक नीतिगत उपक्रम शुरू किया है ।

८. मेरी सरकार ने, महाराष्ट्र को उद्यमिता और नवपरिवर्तन का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए नई "महाराष्ट्र स्टार्टअप, उद्यमिता एवं नवपरिवर्तन नीति-दो हजार पच्चीस" लागू की है। इस नीति का लक्ष्य आगामी पाँच वर्षों में एक लाख, पच्चीस हजार उद्यमियों को प्रोत्साहित करना तथा पचास हजार स्टार्ट-अप्स (Start ups)को सहायता करना है।

९. जनवरी, दो हजार छब्बीस में नीति आयोग द्वारा जारी "निर्यात तत्परता सूचकांक-दो हजार चौबीस" में महाराष्ट्र राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

१०. मेरी सरकार ने, 'महा-इन्विट' (Maha InvIT) (मुलभूत सुविधा निवेश न्यास) स्थापित करने का निर्णय लिया है। उक्त निर्णय के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम और महाराष्ट्र राज्य मुलभूत सुविधा विकास निगम से चयनित मुलभूत सुविधा परियोजना, मुलभूत सुविधा निवेश न्यास में स्थानांतरित करने और निजी तथा सार्वजनिक निवेशकों से निधि जुटाने के लिए मंजूरी दी है । जिससे राज्य का ऋण भार प्रभावी रूप से कम होकर नई मुलभूत सुविधा परियोजना में निवेश बढ़ाने में मदद होगी।

११. मेरी सरकार ने, वर्ष दो हजार पच्चीस-छब्बीस में राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास की गति बढ़ाने के लिए, चार हजार, चार सौ अठहत्तर करोड़ रुपयों के लागत की कुल ग्यारह सौ किलो मीटर लंबाई की एक सौ सैंतालीस प्रमुख सड़क सुधार परियोजनाओं को मंजुरी दी है।

१२. मेरी सरकार ने, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए समृद्धि महामार्ग का विस्तार पालघर जिले के प्रस्तावित वाढ़वण बंदर तक साथ ही पूर्वी विदर्भ के जिलों तक बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है।

१३. मेरी सरकार ने, बंदरों, जहाज निर्माण और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मुंबई में अक्टूबर, दो हजार पच्चीस में आयोजित किये गये "इंडिया मेरिटाइम वीक-

दो हजार पच्चीस” के दौरान लगभग छप्पन हजार करोड़ रुपयों के समझौता करार किए हैं। इससे बंदरगाह विकास और जहाज निर्माण क्षेत्र में निवेश और रोजगार निर्माण को बढ़ावा मिलेगा और भारत की समुद्री क्षेत्र की वृद्धि में महाराष्ट्र की अग्रणी भूमिका और अधिक दृढ़ होगी ।

१४. मेरी सरकार ने, “महाराष्ट्र जहाज निर्माण, जहाज-मरम्मत और जहाज पुनर्उपयोग नीति-दो हजार पच्चीस” की घोषणा की है। इस नीति का उद्देश्य राज्य के समुद्री तटरेखा पर इन क्षेत्रों में परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा देना है।

१५. मेरी सरकार ने, “जीवनयापन में सुगमता” और “व्यापार में सुगमता” की वृद्धि करने के लिए, स्वतंत्रता-पूर्व काल के अनावश्यक कानूनों को निरस्त करने और छोटे स्वरूप के अपराधों के लिए दण्डात्मक प्रावधानों का अपराधमुक्तीकरण तथा उन प्रावधानों को तर्कसंगत बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। यह उपक्रम, नागरिकों और व्यवसायों पर अनुपालन बोझ को कम करने के भारत सरकार के सुधारों के अनुरूप है। एक प्राथमिक कदम के रूप में, “महाराष्ट्र जन विश्वास (उपबंधों में संशोधन) अधिनियम, दो हजार पच्चीस” को अधिनियमित किया गया है।

१६. मेरी सरकार ने, महाराष्ट्र धारित भूमि के विखंडन की रोकथाम और समेकन अधिनियम में संशोधन किया है। इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत, पंद्रह नवंबर, उन्नीस सौ पैंसठ से पंद्रह अक्टूबर, दो हजार चौब्बीस के बीच, किए गये वास्तविक

गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए, उपयोग में लाई गई भूमि का हस्तांतरण तथा विभाजन किसी भी अधिमूल्य की वसूली के बिना नियमित होगा। इससे बड़े पैमाने में शहरी क्षेत्रों के भूमि मालिकों को लाभ मिलेगा और वहाँ भूमि स्वामित्व संबंधी समस्याओं को सुलझाया जायेगा।

१७. मेरी सरकार ने, कर्मचारियों की "नियुक्ति से सेवानिवृत्ति तक" संपूर्ण सेवा संबंधी जानकारी को संगणकीकृत करने के लिए, विभिन्न मानव संसाधन स्त्रोत कार्यों को एकल डिजीटल पोर्टलपर लाने के लिए, "व्यापक डिजिटल परिवर्तन परियोजना" हाथ में ली है।

१८. मेरी सरकार ने, भू-स्थानीक प्रौद्योगिकी के उपयोग द्वारा प्रशासन में गतिशीलता लाने और नीति निर्धारण में त्रुटियाँ कम करने के लिए, महा-जिओटेक ॲप्लिकेशन सेंटर (Maha Geotech Application Centre) की स्थापना की है।

१९. मेरी सरकार ने, पुलिस कर्मी, पुलिस अधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए निवासी आवासों के संनिर्माण हेतु, “पुलिस हाउसिंग टाउनशिप” (Police Housing Township) परियोजना कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है।

२०. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि, राज्य के जल संरक्षण और प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखकर अठारह नवम्बर, दो हजार पच्चीस को सम्माननीय राष्ट्रपति

महोदया द्वारा दिए गए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में "उत्कृष्ट राज्य" की श्रेणी में राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया है।

२१. मेरी सरकार, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में विकास के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए, "मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान" का कार्यान्वयन कर रही है। इस अभियान के अंतर्गत ग्रामपंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पाँच करोड़ रुपयों तक के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे।

२२. मेरी सरकार ने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के माध्यम से, कृषि को अधिक उत्पादक और टिकाऊ बनाने के लिए जून दो हजार पच्चीस से, "महाराष्ट्र कृषि-कृत्रिम बुद्धिमत्ता नीति दो हजार पच्चीस-उनतीस" को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है।

२३. मेरी सरकार, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती अभियान, परम्परागत कृषि विकास योजना तथा डॉ. पंजाबराव देशमुख प्राकृतिक खेती अभियान का प्रभावी रूप से कार्यान्वयन कर रही है। इन योजनाओं के माध्यम से सात हजार, सात सौ छियासी किसान समूहों द्वारा तीन लाख बाईस हजार हेक्टर क्षेत्र में प्राकृतिक खेती की जा रही है।

२४. मेरी सरकार ने, खेत सड़क के संनिर्माण के लिए, "मुख्यमंत्री बळीराजा शेत रस्ते योजना" कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए जैसे बीजारोपण, फसल कटाई और कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुँचाने के लिए मजबूत बारमाही उपयोगी सड़कें बनाई जायेगी ।

२५. सरकार ने, वर्ष दो हजार पच्चीस-छब्बीस के मौसम में भारतीय कपास निगम के माध्यम से एक सौ लाख क्विंटल से अधिक कपास की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की है। मेरी सरकार ने, दो लाख उनतालीस हजार लाभार्थी किसानों से साठ लाख क्विंटल से अधिक सोयाबीन की भी खरीद की है।

२६. मेरी सरकार ने, वर्ष दो हजार चौब्बीस-पच्चीस विपणन सत्र के दौरान, "किमान आधारभूत किंमत खरेदी योजना" के अंतर्गत पंजीकृत किए गए सात लाख से अधिक किसानों को दो हेक्टर की सीमा तक प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रति हेक्टर बीस हजार रुपए वितरित किए हैं।

२७. ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार के अंतर्गत अंतर-बाजार और अंतर-राज्य व्यापार शुरू करने के लिए, 'एकल एकीकृत लाइसेंस' के प्रावधान करने के लिए और राष्ट्रीय दर्जा के बाजार की स्थापना करने के लिए, महाराष्ट्र कृषि उपज विपणन (विकास और विनियमन) अधिनियम, उन्नीस सौ तिरसठ में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।

२८. मेरी सरकार ने, किसानों को दो लाख रुपयों तक के कृषि या फसल ऋण से संबंधित सभी ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है ।

२९. मेरी सरकार ने, राज्य में जून से अक्टूबर, दो हजार पच्चीस के बीच हुई भारी वर्षा और बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदा से प्रभावित हुए किसानों को सहायता देने के लिए, कृषि फसल, कृषि भूमि की हानी तथा आगामी रब्बी मौसम के लिए बीज और अन्य आनुषंगिक मामलों के लिए पंद्रह हजार, पाँच सौ छिहत्तर करोड़ रुपयों की मदद उनके आधार संलग्न बैंक खातों में सीधे वितरीत की है।

३०. मेरी सरकार ने, महाराष्ट्र भू-राजस्व संहिता, उन्नीस सौ छियासठ में संशोधन द्वारा गैर-कृषिक भूमि के उपयोग के लिए अनिवार्य गैर-कृषिक अनुमति तथा सनद संबंधी उपबंध निरसित किए हैं। साथ ही, वार्षिक गैर-कृषिक कर से संबंधित प्रावधान भी निरसित किए गए हैं और भूमि के गैर-कृषिक उपयोग के लिए एक बार रूपांतरण अधिमूल्य वसूल करने संबंधी उपबंध किये हैं।

३१. मेरी सरकार ने, राज्य में सात दशमलव पाँच अश्वशक्ति तक की क्षमतावाले कृषि पंपों का उपयोग करनेवाले किसानों को मुफ़्त बिजली देने के लिए, “मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना” शुरू की है।इस योजना के अंतर्गत सरकार ने, चवालीस लाख से अधिक पात्र किसानों को पच्चीस हजार, सत्तासी करोड़ रुपयों के बिजली शुल्क में राहत दी है।

३२. मेरी सरकार ने, राज्य में “प्रधानमंत्री कुसुम-बी” और “मागेल त्याला सौरपंप योजना” के अंतर्गत छह लाख, तिरसठ हजार, तीन सौ चौब्बीस सौर कृषि पंप बिठाए हैं। सत्ताईस अक्तूबर, दो हजार पच्चीस से पच्चीस नवंबर, दो हजार पच्चीस के बीच पैंतालीस हजार नौ सौ ग्यारह सौर पंप बिठाए गए हैं, जिससे गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ है। सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पाँच दिसंबर दो हजार पच्चीस को गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से यह पुरस्कार स्वीकृत किया है ।

३३. मेरी सरकार ने, सरकारी और निजी भूमि पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भूमि के पट्टा करारों पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फ़ीस में छुट दी है ।इससे, “कृषि को दिन के समय बिजली आपूर्ति मिशन-दो हजार पच्चीस-मुख्यमंत्री सौर कृषि वाहिनी योजना दो दशमलव शून्य” के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया है।

३४. मेरी सरकार ने, प्रति माह एक सौ यूनिट से कम बिजली का उपभोग करनेवाले आर्थिक रूप से कमजोर और गरीबी रेखा के नीचे रहनेवाले बिजली उपभोक्ताओं के लिए, “स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप सोलर योजना” शुरू की है। जिससे, उपभोक्ताओं को उनके छत पर सौर ऊर्जा पॅनल बिठाने के लिए आर्थिक सहायता देकर प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे उनको विद्युत उत्पाद में आत्मनिर्भर बनने में मदद होगी। इस योजना से लाभग्राहियों के बिजली बिल में कटौती होगी और अतिरिक्त सौर ऊर्जा की बिक्री द्वारा उन्हें आय का अतिरिक्त स्त्रोत भी उपलब्ध होगा।

३५.	मेरी सरकार ने, राज्य में वृक्षारोपण बढ़ाने के लिए वर्ष दो हजार पच्चीस में, "हरित महाराष्ट्र, समृद्ध महाराष्ट्र" जन-अभियान शुरू किया है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य में दस करोड़ वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा है। तद्नुसार, इस अभियान के अंतर्गत अब तक लगभग नौ करोड़ अठासी लाख वृक्षारोपण किया जा चुका हैं।

३६.	सरकार ने, 'उमेद' मिशन के अंतर्गत राज्य में, छह लाख साठ हजार महिला स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की है तथा चौंसठ लाख से अधिक परिवारों को चवालीस हजार, दो सौ इक्यावन करोड़ रुपयों का बैंक ऋण उपलब्ध कराया है, जिससे छब्बीस लाख उन्नीस हजार 'लखपति दीदियाँ' हुई हैं। स्वयं सहायता समूह के उत्पादों के लिए सुनिश्चित बाजार उपलब्ध करने हेतु, सभी जिलों में, 'उमेद मॉल्स' स्थापित किए जाएंगे। प्रथम चरण में, तेरह जिलों के लिए 'उमेद मॉल्स' को मंजूरी दी गई है।

३७.	मेरी सरकार ने, आदिवासी महिलाओं को सशक्त करने के लिए, "राणी दुर्गावती महिला सक्षमीकरण योजना" शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना से आदिवासी महिलाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं में आवश्यक लाभार्थी हिस्सा अदा करने में मदद होगी।

३८.	मेरी सरकार ने, भगवान बिरसा मुंडा की एक सौ पचासवीं जयंती के उपलक्ष्य में, 'जनजातीय गौरव दिन' मनाने हेतु संपूर्ण राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया था । साथ ही, राज्य सरकार द्वारा पंद्रह नवंबर से सत्रह नवंबर, दो हजार पच्चीस तक नागपुर में एक राज्यस्तरीय कार्यक्रम का भी आयोजन किया था।

३९. मेरी सरकार, महाराष्ट्र में अन्य पिछड़ा वर्ग, खानाबदोश जनजातियों तथा विशेष पिछड़े प्रवर्गों के छात्रों को कौशल विकास प्रशिक्षण दे रही है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक इकहत्तर हजार से अधिक उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और अठारह हजार से अधिक उम्मीदवारों को रोजगार प्राप्त हुआ है तथा इक्कीस हजार से अधिक उम्मीदवारों ने अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू किया है।

४०. मेरी सरकार ने, राज्य में विकलांग व्यक्तियों के प्रति भेदभाव को समाप्त करने तथा उनकी सामाजिक समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए, विकलांग एवं अविकलांग व्यक्तियों के विवाह के लिए प्रति दंपति एक लाख पचास हजार रुपयों तथा दो विकलांग व्यक्तियों के विवाह के लिए प्रति दंपति दो लाख पचास हजार रुपयों की आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है।

४१. मेरी सरकार ने, राज्य स्वास्थ्य गारंटी सोसायटी से निर्मित आरक्षित निधि योजना के अंतर्गत अंगप्रत्यारोपन शस्त्रक्रिया करने के लिए, प्राधिकृत सरकारी और निजी अस्पतालो में पाँच लाख रुपयों से अधिक लागत की नौ प्रकार की दुर्लभ अंगप्रत्यारोपन शस्त्रक्रियों का उपचार मुफ़्त में करने का निर्णय लिया है।

४२. मेरी सरकार ने, राज्य में कैंसर बिमारी पर सस्ती एवं उन्नत चिकित्सा देने के लिए, एक "व्यापक कैंसर देखभाल नीति" तैयार की है। इस नीति के अंतर्गत त्रि-स्तरीय प्रणाली स्थापित की जा रही है। यह नीति कैंसर विज्ञान के क्षेत्र में प्रशिक्षित

मानव संसाधन विकसित करने तथा कैंसर से संबंधित अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

४३. मेरी सरकार, राज्य में कौशल विकास शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है। "रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय" ने केवल तीन वर्षों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा सायन्स (Data Science), सायबर सुरक्षा, मेकॅट्रॉनिक्स (Mechatronics), औद्योगिक डिझाइन (Industrial Design) और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाओं के साथ नवी मुंबई, पुणे, नागपुर और ठाणे में अपने कार्य का विस्तार किया हैं।

४४. मेरी सरकार ने, माध्यमिक विद्यालय परीक्षाओं के बाद, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए एक शैक्षणिक वर्ष में दो बार सामाईक प्रवेश परीक्षा (सीईटी) (CET) आयोजित करने का निर्णय लिया है। इससे परीक्षा में छात्रों की अनुपस्थिति या अपेक्षित प्रदर्शन न कर पाने के कारण एक शैक्षणिक वर्ष के नुकसान को रोकने में मदद मिलेगी।

४५. मेरी सरकार ने, इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को उच्चतम प्राथमिकता दी है। सरकार ने, सन्माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुखदेव शहा मामले में दिए गए निर्देशनों के संदर्भ में इस गंभीर समस्याओं का निराकरण करने के लिए तेजी से कार्यवाही की है। डॉ. हेमलता बागला समिति द्वारा सिफारिश की

गई 'महाराष्ट्र छात्र सुरक्षा, संरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य कल्याण नीति दो हजार पच्चीस' की स्वीकृती द्वारा सरकार ने सभी विश्वविद्यालयों को यह निर्देश दिया है कि, वे छात्र आत्महत्या रोकने के उपाय करें और उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें।

४६. मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा प्राप्त होने की पार्श्वभूमि में तथा ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों में तकनीकी शिक्षा के प्रति रूची बढ़ाने के लिए, महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड के माध्यम से डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए आवश्यक सभी एक सौ चौवन विषयों के लिए संपूर्ण शैक्षणिक सामग्री मराठी भाषा में अनुवादित की है। अब राज्य में एक सौ बानवे संस्थाओं द्वारा मराठी और अंग्रेजी में शिक्षा दी जा रही है। ऐसी संस्थाओं में मराठी भाषा में अध्ययन करनेवाले छात्रों की संख्या पैंतालीस हजार, चार सौ चवालीस है, अर्थात् कुल प्रवेशित छात्र एक लाख, सात हजार, नौ सौ दस के लगभग बयालीस प्रतिशत है ।

४७. मेरी सरकार ने, अष्टविनायक गणपति मंदिरों, श्री क्षेत्र तुलजाभवानी देवी मंदिर, श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर, जिला अहिल्यानगर के मौजे चौंडी स्थित पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर स्मारक स्थल, जिला नासिक के श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर, कोल्हापुर शहर स्थित श्री करवीर निवासिनी महालक्ष्मी अंबाबाई देवस्थान परिसर तथा श्री क्षेत्र भीमाशंकर के विकास योजनाओं के लिए लगभग तीन हजार, छह सौ इकसठ करोड़ रुपयों की प्रशासनिक मंजूरी दी है।

४८. मेरी सरकार ने, सिंहस्थ कुंभमेला दो हजार सताईस-अठाईस के सुचारू एवं सुव्यवस्थित आयोजन करने के लिए, अधिनियम की अधिनियमिति द्वारा एक "कुंभमेला प्राधिकरण" की स्थापना की है। यह प्राधिकरण यात्रियों के लिए परिवहन, स्वास्थ्य सेवा, जल आपूर्ति और सुरक्षा जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं का आयोजन और प्रबंधन करेगा।

४९. मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि, सत्तहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर हुए परेड़ में महाराष्ट्र के "गणेशोत्सव : आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक" इस चित्ररथ ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है।

५०. मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि, छत्रपति शिवाजी महाराज के युग के मराठा लष्कर की वास्तुकला की उत्कृष्टता को मान्यता देते हुए महाराष्ट्र राज्य के राजगड़, रायगड़, प्रतापगड़, साल्हेर, लोहगड़, शिवनेरी, पन्हाला, खांदेरी, सुवर्णदुर्ग, सिंधुदुर्ग और विजयदुर्ग तथा तमिलनाडु का जिंजी किला ऐसे कुल बारह किलों को युनेस्को के वैश्विक विरासत सूची में शामिल किया गया है।

५१. मेरी सरकार ने, राज्य में किला पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य के पचहत्तर स्थानों पर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित नमो पर्यटन सूचना एवं सुविधा केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।

५२. मेरी सरकार ने, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर की तीन सौ वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके जीवन पर आधारित मराठी तथा अन्य भाषाओं में एक फीचर फिल्म निर्माण करने का निर्णय लिया है।

५३. मेरी सरकार ने, वर्ष दो हजार पच्चीस में श्री गुरू तेग बहादुर साहिबजी के तीन सौ पचास वें शहादत दिवस की स्मृति में नागपुर और नांदेड़ में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इन उपक्रमों का उद्देश्य, उनके गौरवशाली इतिहास को सभी तक पहुँचाना तथा उनके उपदेशों और सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देना है।

५४. "महाराष्ट्र राज्य सांस्कृतिक नीति-दो हजार चौब्बीस" का कार्यान्वयन करने की दृष्टि से मेरी सरकार ने, महाराष्ट्र के सभी छत्तीस जिलों में जिला साहित्य संमेलन आयोजित करने हेतु प्रति जिले, पाँच लाख रूपयों का अनुदान प्रतिवर्ष मंजूर करने का निर्णय लिया है ।

५५. मेरी सरकार विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर क्रीड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है। मेरी सरकार ने, शतरंज की विश्व चैंपियन एवं ग्रैंडमास्टर कुमारी दिव्या देशमुख साथ ही, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियाँ कुमारी स्मृति मंधाना, जेमिमा रॉड्रिग्स और राधा यादव को और मुख्य कोच अमोल मुजुमदार को ऐतिहासिक विश्वकप जीत के लिए नक़द राशि देकर सम्मानित किया गया है।

५६. मेरी सरकार ने, पहला टी-ट्वेंटि दृष्टिहीन महिला विश्वकप जीतने की ऐतिहासिक उपलब्धि पर भारतीय दृष्टिहीन महिला क्रिकेट टीम तथा उसमें से महाराष्ट्र के हिंगोली जिले की खिलाड़ी कुमारी गंगा कदम को सम्मानित किया है।

५७. मेरी सरकार, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर एक समावेशी, प्रगतिशील एवं विकसित महाराष्ट्र के निर्माण के लिए कार्य कर रही है।

५८. सम्माननीय सदस्यों, इस सत्र में, नए वित्तीय वर्ष के लिए बजट प्रस्तावों, विनियोग विधेयक और अन्य विधिविधान आपके विचारार्थ रखे जाएंगे। मुझे विश्वास है कि, महाराष्ट्र को अधिक समृद्धि की ओर ले जाने के लिए सम्माननीय सदस्य कामकाज में भाग लेंगे और इन प्रस्तावों पर अपने उचित विचार-विमर्शों को प्रदर्शित करेंगे।

मैं फिर से एक बार, आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

जय हिंद। जय महाराष्ट्र ।।